जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 48 संख्याः 322 प्रभात कोटा, मंगलवार 5 सितम्बर, 2023 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से 100 साल पहले गायब हुए क्वॉल की वापसी हो रही है। लम्बे थूथन वाले ये झबरीले जानवर ऑस्ट्रेलिया के मांसाहारी मार्सूपिअल जीवों की एक प्रजाति हैं। ये बिल में या गुफाओं में रहते हैं और रात में शिकार करते हैं। मार्सूपिअल जीव पेट पर बनी थैली में शिशुओं का पालन पोषण करते हैं। वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के 1305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली माउण्ट गिब्सन वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में इस वर्ष के आरंभ में 30 वैस्टर्न क्वॉल छोड़े गए थे, वो न केवल जंगल में खूब अच्छी तरह से रह रहे हैं बल्कि प्रजनन भी कर रहे हैं। माउन्ट गिब्सन रिज़र्व में किया गया ''रीइन्ट्रोडक्शन'' प्रयास ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का ऐसा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यहां अलग-अलग प्रजाति के जानवर छोड़ गए हैं जो ऑस्ट्रेलियन वाइल्डलाइफ कंज़र्वैन्सी के लिए बड़ी उपलब्धि है। रिज़र्व में छोड़े जाने से पहले 16 क्वॉल को रेडियो ट्रैकिंग कॉलर्स लगाए गए थे। पहली बार वैस्टर्न क्वॉल पर यह तरीका लागू किया गया। इससे क्वॉल्स कहां जाते हैं, कहा रहते हैं और कहां शिकार करते हैं, यह पता लगाने में काफी आसानी हुई। ऑस्ट्रेलिया के स्तनपायी जीवों की कई प्रजातियां अभी भी संकटग्रस्त हैं पर कुछ प्रजातियों की स्थिति में सुधार हो रहा है। इनमें टालपेरु (छोटा बैंडीकूट) जैसे जानवर हैं, जो 100 साल गायब रहने के बाद स्टुअर्ट नैशनल पार्क में लौटे हैं।

क्या शी जिनपिंग विश्व रंगमंच पर ''आईसोलेट'' कर दिए जाने के डर से जी-20 में नहीं आ रहे हैं?

विश्व भर के कूटनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि, चीन के अपडेटेड नक्शे का पूरे क्षेत्र में भारी विरोध हुआ, इसलिए शी कहीं भी जाने से कतरा रहे हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नई दिल्ली के जी-20 सम्मेलन में न आना भारत का अपमान है? या फिर, उनका यह कदम उनकी असुरक्षाओं एवं आशंकाओं से भरी सोच को दर्शाता है?

कूटनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि, राष्ट्रपति शी ने विश्व रंगमंच पर स्वयं को अलग-थलग या एकल कर लिया है। दसअसल, वे नई दिल्ली के जी-20 सम्मेलन के साथ ही, जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित आसियान इंडिया तथा ईस्ट एशिया सम्मेलनों से दूर रहने का मानस बना चुके हैं।

चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी (सी.सी. पी.) इस समय राजनैतिक अस्थिरता तथा अंदरूनी लड़ाई की स्थिति से गुजर रही है। इस स्थिति के चलते, शी को अपने देश में समय देना जरूरी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे हुये हैं।

दक्षिणी चीन सागर में बेबुनियाद दावे तथा अपने भौगोलिक नक्शे के ''अपडेटेड'' संस्करण के जारी कर दिये जाने के कारण, करीब-करीब सारे

- **कुछ विशेषज्ञों का मत है कि, शी संभवतया या तो गंभीर रूप से बीमार हैं या फिर घरेलू मोर्चे पर भारी राजनैतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, इसीलिए वे कहीं भी जाने से हिचक रहे हैं।**
- **शी जिनपिंग 6 सितम्बर को हो रहे आसियान सम्मेलन में भी नहीं जायेंगे। चीन के नक्शे में जिस तरह से दक्षिण चीन सागर व क्षेत्र के अन्य देशों की जमीन पर दावा किया गया है, उसकी वजह से ये सभी देश बेहद नाराज हैं, ऐसे में निस्संदेह शी जिनपिंग का वे हृदय से स्वागत तो नहीं ही कर पाएंगे।**

''आसियान'' राष्ट्रों को नाराज कर देने के बाद, शी के आसियान सम्मेलन में जाने की पहले दिन से ही कोई संभावना नहीं थी। बीजिंग ने कल्पना भी नहीं की होगी कि, उसके द्वारा जारी नक्शे को लेकर, भारत एवं ताइवान के विरोध के बाद, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस भी एक स्वर में नक्शे के विरोध में शामिल हो जायेंगे।

शी के एकान्तवास के ठीक विपरीत, प्रधानमंत्री का रणनीतिक कौशल अपनी पराकाष्ठा पर दिखाई दे रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री तथा पूरा देश जी-20 की अध्यक्षता की उपलब्धि को पूरी रणनैतिक कुशलता के साथ विश्व के सामने रख रहा है।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मोदी ने नौ सरकारी विदेश यात्राएं करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि भारत का कूटनीतिक तंत्र कितने जोर-शोर से काम कर रहा है। पहले वे जी-7 एवं क्वाड मीटिंगों के सिलसिले में जापान गये थे और उसके बाद पापुआ न्यूगिनी तथा ऑस्ट्रेलिया। और इन सबसे बढ़कर, उनकी अमेरिका की सरकारी यात्रा रही, जहां राष्ट्रपति जो बाइडन ने बड़ी धूमधाम एवं भव्यता के साथ उनका जोरदार स्वागत किया था। जुलाई में, मोदी फ्रांस गये थे, जहां वे राष्ट्रपति मैक्रॉन के साथ ''बैस्टिल डे'' समारोह में शामिल हुये थे। फ्रांस के बाद, उन्होंने यू.ए.ई. की संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण यात्रा की थी। अगस्त में, प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में गये थे तथा इसके बाद, वे ग्रीस गये थे। उनकी ग्रीस यात्रा पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी।

जी-20 के लिये उलटी गिनती शुरू हो गई है तथा सम्पूर्ण तैयारी को अंतिम स्पर्श दिया जा रहा है। भारत का गेम-प्लान स्वयं को ''ग्लोबल साउथ'' की आवाज के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री मोदी आसियान तथा ईस्ट एशिया सम्मेलनों में शामिल होने के लिये 6 सितम्बर को इंडोनेशिया भी जायेंगे। उल्लेखनीय है कि मोदी ने नई दिल्ली के जी-20 सम्मेलन से ठीक पहले, आसियान नेताओं के साथ अपने जुड़ाव को रेखांकित करना उचित तथा आवश्यक माना है।

पक्की बात है कि इस वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रहने से मोदी काफी उत्साहित हैं। अगली कुछ तिमाहियों में अर्थव्यवस्था के और भी बेहतर रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं।

मणिपुर सरकार ने एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष और उसके तीन पत्रकारों पर एफ.आई.आर. दर्ज की

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह ने एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में इन पत्रकारों पर पक्षपात पूर्ण रिपोर्टिंग करने व राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। प्रेस की आज़ादी पर निर्लज्जता से एक और हमला बोलते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने आज कहा कि उनकी सरकार ने एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ई.जी.आई.) के अध्यक्ष और तीन सदस्यों के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई हैं। उन्होंने इन पत्रकारों पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया।

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इंफाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसे समय में जब कई लोग मारे गए हैं और बेघर हो गए हैं तब ई.जी.आई. ने के संकट की जटिलता और राज्य की पृष्ठभूमि और इतिहास को जाने बिना एकतरफा रिपोर्ट प्रकाशित की है।

- **जिन पत्रकारों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, वो हैं, एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा, सीमा गुट्टा, भारत भूषण एवं संजय कपूर।**
- **एन. बीरेन सिंह ने इन पत्रकारों पर राजद्रोही, राष्ट्र विरोधी व सरकार विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि, वे राज्य में जहर उगलने ही आए थे।**

सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने मोदी सरकार के शीर्ष नीति निर्धारकों के साथ मुख्यमंत्री की व्यापक चर्चा के बाद यह कदम उठाया। यह कदम एक सख्त संदेश भेजने का प्रयास है। मीडिया के उस वर्ग को जो अभी भी स्वतंत्रता से काम कर रहा है और सत्ता के आदेशों के आगे नहीं झुकता।

एडीटर्स गिल्ड ने गत सप्ताह एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें मणिपुर की कवरेज के लिए मीडिया की आलोचना की गई है, जहां गत चार माह से जातीय संघर्ष हो रहा है। रिपोर्ट में कुछ मीडिया वर्ग द्वारा एकतरफा रिपोर्टिंग की आलोचना की गई है और प्रेस के लिए नुकसानदाय इंटरनेट बैन को गलत बताया गया है कि यह प्रेस की रिपोर्टिंग के लिए घातक है। उसमें संकेत हैं कि संघर्ष के दौर में राज्य नेतृत्व पक्षपाती हो गया है।

सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''राज्य सरकार ने एडीटर्स गिल्ड के उन सदस्यों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है जो मणिपुर राज्य में टकराव बढ़ाना चाहते हैं।''

ई.जी.आई. की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा के अलावा तीन वरिष्ठ पत्रकारों सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन्होंने 7 से 10 अगस्त के बीच राज्य का दौरा किया था। हिंसा पर मीडिया के रिर्पोट्स का अध्ययन के लिए।

सिंह ने दावा किया, वे लोग राज्य-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी और संस्थापन-विरोधी हैं जो विष फैलाने आए है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनको घुसने ही नहीं देता।''

ई.जी.आई. ने शनिवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे कई खबरें मिली थीं कि मणिपुर में मीडिया मैइती और कुकी समुदाय के बीच चल रहे संघर्ष में पक्षपाती रवैया अपना रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ''इस बात के स्पष्ट संकेत है कि संघर्ष के दौरान राज्य का नेतृत्व पक्षपाती हो गया। उसे किसी का पक्ष लेने से बचना चाहिए था लेकिन वह एक लोकतांत्रिक सरकार साबित होने में असफल रहा, जिसे पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।''

ई.जी.आई. की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में पत्रकारों द्वारा दी गई खबरों की जाँच और निगरानी उनके संपादक या ब्यूरो प्रमुख करते हैं, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों से जानकारी लेकर लेकिन संघर्ष के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है?
ऑटोमेटिक
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
कॉकलियर इम्पलांट, ऑटिजम
डिले स्पीच, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क- 94602 07080

'एडिटर्स गिल्ड पर एफ.आई.आर. निन्दनीय'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। प्रैस क्लब ऑफ इंडिया ने एडीटर्स गिल्ड के अध्यक्ष व तीन सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. तुरंत वापस लेने की मांग की और मणिपुर की हिंसा व जातीय टकराव की मीडिया कवरेज के लिए उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज न करने की निंदा की।

- **प्रैस क्लब ऑफ इंडिया ने मणिपुर सरकार के इस कदम की आलोचना की और रिपोर्ट वापस लेने की मांग की।**

प्रैस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने कहा कि, समूचा मामला मीडिया की भूमिका पर केन्द्रित है। और यह स्पष्ट है कि एडिटर्स गिल्ड ने शानदार काम किया व तथ्यों की जांच करने वाली टीम मणिपुर भेजी ताकि वहां की सरकार जो सच्चाई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'एक राष्ट्र एक चुनाव असंभव'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि संविधान संशोधन के बिना ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' असंभव है।

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के विचार एक दम स्पष्ट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि यह संघीय ढांचे पर प्रहार है।

- **कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पत्रकारों से कहा कि, संविधान संशोधनों के बिना ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' करवाना नामुमकिन है।**

उन्होंने कहा, विशेष सत्र से पूर्व पार्टी की संसदीय दल की 10, जनपथ पर एक बैठक होगी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सत्र के लिए रणनीति पर विचार हेतु समान विचारधारा वाले दलों के साथ बैठक करेंगे।

दो महिला नेताओं की नाराजगी भारी पड़ सकती है भाजपा को

सूत्रों के अनुसार राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में उमा भारती भाजपा नेतृत्व से नाराज़ बताई जा रही हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। भाजपा नेतृत्व दो चुनावाधीन राज्यों में दो वरिष्ठ महिला नेताओं-राजस्थान में वसुंधरा राजे तथा मध्य प्रदेश में उमा भारती-के कारण साफतौर पर परेशानी में है। राजे दो कारणों से अप्रसन्न बताई जाती हैं- चुनाव से संबंधित पार्टी की दो कमेटियों में उन्हें शामिल न किया जाना तथा उन्हें मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में प्रोजैक्ट नहीं करने की पार्टी नेतृत्व की अविवेकपूर्ण कोशिशें। उमा भारती, जिनकी राजनीति बहुत कम अर्थपूर्ण रह गई है, न इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की है कि उन्हें पार्टी की ''जन आशीर्वाद यात्रा'' में शामिल होने के लिये आमंत्रित नहीं किया गया, जो रविवार को चित्रकूट से शुरू हुई थी।

- **जहां राजस्थान में वसुंधरा राजे बेहद प्रभावशाली हैं और पार्टी द्वारा दो कमेटियों से बाहर रखने व भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किए जाने से नाराज हैं, इसलिए भाजपा नेतृत्व राजे से सतर्क है।**
- **मध्य प्रदेश में उमा भारती भी उपेक्षित किए जाने से नाराज़ हैं, हालांकि उमा भारती का अब वह दबदबा नहीं रहा जो वाजपेयी-अडवानी के दौर में था, पर वे कई सीटों पर भाजपा का परेशानी में डाल सकती हैं।**

उन्होंने कहा है कि अब अगर उन्हें आमंत्रित किया भी जाता है, तो भी वे यात्रा में शामिल नहीं होंगी। राजे और भारती-दोनों में ही इतनी क्षमता है कि, वे इन दोनों राज्यों में भाजपा की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन इन दोनों में समानताएं केवल यहीं तक हैं।

जहां भाजपा हाई कमान राजे, जो राजस्थान में भाजपा की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, से सावधान एवं सतर्क रहता है, वहीं उमा भारती नाम मात्र के महत्व के अलावा किसी खास स्थिति में नजर नहीं आती। उमा भारती, जो 2003-04 में अपने राजनैतिक उत्कर्ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक राष्ट्र-एक चुनाव का मुद्दा उछालने की ''टाइमिंग'' पर संदेह गहरा रहा है

चर्चा यह है कि, ''एक राष्ट्र-एक चुनाव'' कई वर्षों से संघ परिवार व मोदी का प्रिय रहा है, फिर इसे अभी क्यों उठाया गया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। गत 31 अगस्त को जब लोगों का ध्यान इंडिया गठबंधन की दो-दिवसीय बैठक की ओर था तब मोदी सरकार ने लोगों का ध्यान बंटाने के लिए केन्द्रीय संसदीय मामलात मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा करवाई कि सितम्बर 18-22 तक संसद का विशेष सत्र होगा।

जोशी ने अपने ट्विटर पर आगे लिखा कि अमृतकाल के बीच पांच बैठकें होंगी और व संसद में फलप्रद चर्चा और बहस की उम्मीद है। लेकिन वे इस कवायद के प्रयोजन एवं उद्देश्य के बिन्दुओं पर खामोशी ओढ़े रहे।

अगले दिन जब हर तरफ विशेष सत्र की चर्चा थी तब सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव का शगूफा छोड़ा, पर विशेष सत्र की पहेली नहीं सुलझाई। शुक्रवार, एक सितम्बर को सरकारी सूत्रों ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में कमेटी गठित होने की जानकारी दी थी।

कोई अधिकृत सूचना तो नहीं थी, हाँ, एक मीडियाकर्मी के प्रश्न के जवाब में एक मंत्री का मौखिक कथन जरूर था और सरकार ने इससे इनकार नहीं किया पर यह बिल्कुल साफ था कि विशेष सत्र

- **आगामी चुनावों में इसे क्रियान्वित करना असंभव है, क्योंकि ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन व कानून के क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी।**
- **सवाल यह भी उठ रहा है कि, क्या इसी उद्देश्य के लिए भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा व संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात की थी।**
- **पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में कमेटी का गठन संवैधानिक परम्पराओं का उल्लंघन बताया जा रहा है, क्योंकि संविधान में पूर्व राष्ट्रपति को कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करने की हिदायत दी गई है, ताकि वे निष्पक्ष बने रह सकें, पर कोविंद ने कमेटी की अध्यक्षता स्वीकार कर यह परम्परा तोड़ दी है।**

तथा एक राष्ट्र एक चुनाव- दोनों बातों का ही त्वरित उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना तथा ''एक नया समाचार चक्र शुरु करना था।

शनिवार को, सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यों की एक कमेटी की घोषणा कर दी, जो लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे का अध्ययन एवं परीक्षण करेगी।''

यह एक संयोग मात्र नहीं हो सकता कि भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा तथा आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत ने उसी सप्ताह में कोविंद के साथ मीटिंग की थी, जब सरकार इस कार्यवाही की योजना बना रही थी। एक पूर्व राष्ट्रपति को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर, मोदी सरकार ने एक बार फिर उन संवैधानिक परम्पराओं को अलविदा कह दिया है, जिनमें देश के सेवानिवृत्त प्रमुख पर साफतौर पर प्रतिबंध लगाते हुये कहा गया है कि वे निष्पक्ष बने रहेंगे। एक ऐसे विवादास्पद मुद्दे, जिस पर राजनैतिक दल बँटे हुये हैं, पर सरकार द्वारा गठित एक कमेटी की अध्यक्षता स्वीकार कर के, कोविंद ने भी अतीत की उन परम्पराओं को अलविदा कह दिया है तथा संकीर्ण राजनैतिक तथा तरफदारी के लिये अपने उपयोग की छूट दे दी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

16-17 सितम्बर को हैदराबाद में होगी सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नवगठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक 16 सितम्बर को हैदराबाद

- **कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 16 सितम्बर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी व 17 को विस्तृत वर्किंग कमेटी की बैठक होगी।**

में बुलाई है। 17 सितम्बर को विस्तृत सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक होगी। सी. डब्ल्यु.सी. के सारे सदस्य, पी.सी.सी. अध्यक्ष, सी.एल.पी. नेता और संसदीय दल के पदाधिकारी इसमें भाग लेंगे। यह जानकारी सोमवार को कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने दी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)